



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 15 नवम्बर, 2008 / 24 कार्तिक, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 1 नवम्बर, 2008

संख्या एस.जे.ई.-ए (3) 8/2005.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तकु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में तहसील कल्याण अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, तहसील कल्याण अधिकारी वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू. एल. एफ.-ए (3)—9/87, तारीख 28-2-1992 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश समाज एवं महिला कल्याण विभाग, तहसील कल्याण अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध—क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में तहसील कल्याण अधिकारी वर्ग-II (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—तहसील कल्याण अधिकारी
2. पदों की संख्या.—69(उनहत्तर)
3. वर्गीकरण.—वर्ग-II
4. वेतनमान.—रुपये 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—चयन पद ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्पूर्व ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.—(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद/पदों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:—(क) अनिवार्य अर्हता:—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।

(ख) **वांछनीय अर्हताएं:—** हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं:—आयु:—लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता:—लागू होगी ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति:—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता:—(1) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

(2) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार या संविदा के आधार पर ।

11 प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा:—(i) तीस प्रतिशत वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(ii) बीस प्रतिशत पर्यवेक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

प्रोन्नति और सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस बिन्दू रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:—

वरिष्ठ सहायक पहला, पांचवां, नवां
पर्यवेक्षक	... दूसरा और छठा
सीधी भर्ती	... तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां और दसवां

प्रत्येक 10वें पद के पश्चात् रोस्टर दोहराया जाएगा जब तक सभी वर्गों को दी गई प्रतिशतता के अनुरूप प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता । तत्पश्चात् पद उसी वर्ग से भरा जाएगा जिस द्वारा यह खाली किया जाएगा ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों का जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण:—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया है तथा इनके अधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक पद पर गई निरन्तर तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, जो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, इत्यादि यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15 -क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—(I) संकल्पना (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में तहसील कल्याण अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

नया उपबन्ध (ख) निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त तहसील कल्याण अधिकारी को 9600/— रूपए की संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200/— रूपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 9600/— रूपए नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 200/— रूपए वार्षिक की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति आरै एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगी केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(ङ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में तहसील कल्याण अधिकारी के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेदन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध—ख

तहसील कल्याण अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का परूप

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने तहसील कल्याण अधिकारी के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार तहसील कल्याण अधिकारी के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा।

यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, अन्तिम कार्य दिवस् को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 9600/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
6. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्यों (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
7. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दारै पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./जी. पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षरित किया गया।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of this department notification No. SJE-A(3)8/2005, dated -----
-----as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st November, 2008

No. SJE-A(3)8/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Tehsil Welfare Officer, Class-II(Non-Gazetted)in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Tehsil Welfare Officers,Class-II-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 2008.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Social & Women's Welfare Department, Tehsil Welfare Officer(Class-III-Non-Gazetted) Recruitment and Promotion rules, 1992 notified vide this Department notification No. WLF-A(3)-9/87 dated 28.2.1992 are hereby repealed.

(2)Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Sd/-

Pr. Secretary(SJ&E).

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TEHSIL
WELFARE OFFI (NON-GAZETTED) CLASS-II IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL
JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH**

- 1. Name of the Post**—Tehsil Welfare Officer.
- 2. Number of posts**—69 (Sixty nine).
- 3. Classification**—CLASS-II (Non-Gazetted).
- 4. Scale of pay**—6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.
- 5. Whether Selection or Non-Selection post**—Selection.
- 6. Age for direct recruitment**—Between 18 & 45 years .

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit. —(a)
ESSENTIAL QUALIFICATIONS: Should be a graduate from a recognised University.

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS : Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age:----- No. Educational qualification Yes.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be record in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.—(i) 50% by promotion. (ii) 50% direct recruitment on regular basis or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—(i) 30% By promotion from amongst the Sr. Assistants having five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade.

20% by promotion from amongst the Supervisors having 8 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade.

For the purpose of promotion & direct recruitment the following 10 point roster will be applied:

Senior Assistant:	1,5,9
Supervisor:	2&6
Direct recruitment:	3,4,7 ,8&10. (10 point roster).

The roster will be rotated after every 10 point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that:

(i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the persons(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—DPC to be presided over by the chairman H.P. Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. —As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting agency as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.
(i) CONCEPT.

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment.— (a) Under this policy, the Tehsil Welfare Officer in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) **Post Falls Within The Purview of HPPSC :** The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job.

(ii) **Contractual Emoluments :** The Tehsil Welfare Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 9600/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs 200/- as per annual increase in contractual

emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(iii) **APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY** : Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(iv) **SELECTION PROCESS** : Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPPSC.

(V) **COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS** : As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.P.S.C. from time to time.

(VI) **AGREEMENT** : After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) **TERMS AND CONDITIONS:** (a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.9600/- per month(which shall be equal to initial of the pay scale+ dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 200/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given .

(b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled for TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT: The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/ permanent absorption as Tehsil Welfare Officer in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— N.A.

18. Powers to Relax.—Where the State Government. Is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Tehsil Welfare Officer Government of Himachal Pradesh through Social Justice & Empowerment Department

This agreement is made on this-----day of -----in the
year.....Between
Sh/Smt./Km.....S/o/D/o.....Shri.....R/o.....
.....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The
Governor, Himachal Pradesh through Director, Social Justice and Impowerment Himachal
Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) whereas the second party has engaged the
aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Tehsil Welfare Officer
on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Tehsil Welfare Officer for a period of 1 year commencing on day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on..... And information notice shall not be necessary.
2. The contractual emoluments of the FIRST PARTY will be Rs. 9600/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.
4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.
5. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. No other leave of any kind is admissible to the contractual appointee.

He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. The contractual appointee will not be entitled for salary for the period of absence from duty.
7. Transfer of the contractual appointee on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
9. Contractual appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Officer at the minimum of pay scale.
10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s). In Witness thereof, the Party to the agreement have put their hands on the day month and the year above written.

In the presence of Witness:

1 -----

(name & full address)

2. -----

(name & full address)

(Signature of the Ist Party)

In the presence of witness:

1 -----

(name & full address)

2. -----

(name & full address)

(Signature of the IInd Party).

संख्या एस.जे. ई. ए(3)12/2005.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सहायक अधीक्षक (गृह) वर्ग—III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहायक अधीक्षक (गृह) वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू. एल. एफ.—ए(3)—16/87, तारीख 22.12.97 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश समाज एवं महिला कल्याण विभाग, सहायक अधीक्षक (गृह) वर्ग—III, (अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 तथा समय—समय पर संशोधित का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप—नियम(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध—क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सहायक अधीक्षक (गृह) वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

- 1. पद का नाम.**—सहायक अधीक्षक (गृह)
- 2. पदों की संख्या.**—5 (पांच)
- 3. वर्गीकरण.**—वर्ग—III (अराजपत्रित)
- 4. वेतनमा.**—5000—160—5800—200—7000—220—8100 रुपए (विस्तृत रूप में दिया जाए।)
- 5. चयन पद अथवा अचयन पद.**—अचयन पद ।
- 6. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी;

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गई हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलेन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कमचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए गए हैं/किए गए थे ।

(i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद/पदों का आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं—अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष तथा भारत के किसी भी राज्य में सरकार द्वारा संचालित रजिस्ट्रीकृत किसी भी स्वयंसेवी संस्थान में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय अर्हताएं—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति किए गए व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं—आयु : लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता—लागू नहीं

9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो—दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणिया (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा—(1) 40 प्रतिशत प्रोडक्शन युनिट गार्ड—कम—टीचर/क्राफ्ट टीचर में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

(2) 60 प्रतिशत महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

पदों को भरने हेतु निम्न पांच बिन्दू रोस्टर विहित किया जाएगा।—पहला तथा दूसरा पद प्रोडक्शन यूनिट गार्ड—कम—टीचर/क्राफ्ट टीचर को।

तीसरा, चौथा तथा पाचवां पद महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को।

रोस्टर हर पांचवें बिन्दू के बाद दोहराया जाता रहेगा जब तक कि सभी प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। इसके पश्चात रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद खाली होता हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी।

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे।

परन्तु उन सभी पदधारियों का जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तु की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम -3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी।

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—

(I) संकल्पना.—(क) इस पालिसी के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश में सहायक अधीक्षक(गृह) संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पदों का हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रिक्त पद(पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमले न का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अधीक्षक (गृह) को 7,500/— रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम जो वेतनमान के आरम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी प्रतिमास संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 160/— रुपए की वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर व पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक कर्मचारी के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हि. प्र. अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन एवं शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7,500/— रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो मूल वेतनमान के आरम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 160/— रुपए की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा। और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकारी प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.—इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में सहायक अधीक्षक (गृह) नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—ख

सहायक अधीक्षक (गृह) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति.....पुत्र / पुत्री श्री.....निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक अधीक्षक (गृह) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अधीक्षक (गृह) के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार को 7500/— रुपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित)की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण के लिए पदधारी को कोई अधिकार पदान नहीं करेगी।
5. संविदा पर नियुक्त सहायक अधीक्षक (गृह) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
6. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति कर्तव्यों (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।
7. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए किसी भी दशा में स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है वेतनमान के न्यूनतम पर, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ—साथ इ.पी.एफ./जी. पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में उल्लिखित तारीख को आपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English Text of this department notification NoSJE-A(3)12/2005, dated----- as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 22 April, 2008

No. SJE-A(3)12/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Assistant Superintendent(Home), Class-III(Non-Gazetted)in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1)These Rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department,Assistant Superintendent(Home),Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 2007.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Social Justice & Women's Welfare Department, Assistant Superintendent (Home),(Class-III Non- Gazetted)Recruitment and Promotion rules, 1997 notified vide this Department notification No. WLF-A(3)- 16/87 dated 22.12.1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT SUPERINTENDENT (HOME) (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPLOYMENT, HIMACHAL PRADESH.

1. *Name of the Post.*—Assistant Superintendent (Home)
2. *Number of posts.*—5 (Five)
3. *Classification.*—Class- III (Non-Gazetted)
4. *Scale of pay (be given in expanded notation).*—5000-160-5800-200-7000-220-8100
5. *Whether Selection or Non-Selection post.*—Non-Selection.
6. *Age for direct recruitment.*—Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment; Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/Autonomous Bodies.

- (i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

- (ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—

a) ESSENTIAL.—Bachelor's Degree from a recognized University or its equivalent with 3 years working experience in any of the registered voluntary Institution run by the Govt. In any State of India.

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes.—Age.—N.A

Educational qualification----- N.A

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which Direct recruitment or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—(i) 40% by promotion from amongst the production unit guide-cumteachers/Craft Teachers who possess 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any, in the grade.

(ii) 60% by promotion from amongst the lady social workers who possess 7 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.

For the purpose of promotion, the following five point roster shall be prescribed:-

1st and 2nd point Production unit guidecum-teacher/ Craft teacher 3rd, 4th and 5th posts lady social workers.

The roster will be rotated after every 5th point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that;

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service(including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service /appointment)in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to

him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the persons(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, (1972 and having been given the benefit of seniority) there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal State Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. If the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. *If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.*—As may be constituted by the Government from time to time.

13. *Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.*—As required under the law.

14. *Essential requirement for direct recruitment.*—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment.*—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting authorities as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.

15-A. *Selection for appointment to the post by contract appointment.*—**(I) CONCEPT.**—
(a) Under this policy, the Assistant Superintendent(Home)in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) **Post Falls Within The Purview of HPSSB.**—The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P.Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Superintendent (Home) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 7500/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs 160 as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPSSB.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.S.S.B. from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7500/- per month(which shall be equal to initial of the pay scale +dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 160/- per annum for second and their years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any state.

(d) Contractual appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stay temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/permanent absorption as Assistant Superintendent(Home) in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Superintendent (Home) & the Government of Himachal Pradesh through Director Social Justice & Empowerment Department

This agreement is made on this-----day of -----in the year.....Between Sh/Smt./Km.....S/o/D/o.....Shri.....R/o.....
.....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Social Justice and Empowerment Himachal Pradesh(here-in-after the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Superintendent (Home..) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Superintendent(Home) for a period of 1 year commencing on day of..... and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on..... And information notice shall not be necessary.
2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs.7500 Per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.
5. Contractual appointee .(Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the Contractual appointee (Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee (Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
9. Contractual appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart Official at minimum of pay scale.
10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and Full Address)

(Signature of the First party)

2.

 (Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

2.

 (Name and Full Address)

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 01 नवम्बर, 08

संख्या ई.डी.एन.सी-ई (3)-1/2007.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा नारी तहसील, अम्ब, जिला ऊना हि० प्र० में राजकीय प्राथमिक पाठशाला नारी (चिन्तपूर्णी) हि० प्र० के भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित भूमि अर्जित करना अपेक्षित है । अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्रा में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त परियोजन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप मण्डल अधिकारी (ना०) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने के एतद् द्वारा निर्देश किया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, उप मण्डलाधिकारी (ना०) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
ऊना	अम्ब	नारी (चिन्तपूर्णी)	725	0-17-44
			736	0-01-10
			किता-2	0-18-54 गैर मुमकिन

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव ।